भूकंप-पीड़ितों के लिए पुनर्वास परियोजना हेतु विश्व बैंक की सहायता

3760. **श्री सुशीलकुमार संभाजीराव सिंदे** : क्या वित्त मंत्री 8 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 2091 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के भूकंप-पीड़ितों के लिए आपात पुनर्वास परियोजना हेतु इसकी सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ अपनी बातचीत पूरी कर ली है, यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) महाराष्ट्र में भूकंप-पीड़ितों के पुनर्वास हेतु विश्व के देशों द्वारा भेजी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : (क) और (ख) जी, हां। 246.00 मिलियन अमरीकी डालर के औद्योगिक विकास संघ के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ एक करार महाराष्ट्र के भूकम्प-पीड़ितों के लिए आपात पुनर्वास परियोजना हेतु हस्ताक्षरित हुआ है।

विभिन्न देशों/संगठनों (विश्व बैंक सहित) द्वारा महाराष्ट्र में भूकम्प से राहत के लिए प्रस्तावित सहायता की कुल राशि अब लगभग 859.8 करोड़ रुपए बैठती है।

Hike in Service Charges of Public Sector Banks

3761. SHRI SOM PAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are allowing the public sector banks to effect a steep hike in their service charges ;

(b) if so, what are the details and rationale thereof ;

(c) whether any steps are taken/being taken to bring about improvement in the quality of services offered by the banks to consumers and depositors ; and

(d) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) Based on the recommendations of the Committee of Public Sector Banks on Service Charges, all public sector banks have adopted a common schedule of service charges which lays down the minimum that can be charged. It has been left to the discretion of individual banks to selectively levy higher charges if special circumstances so warrant. The service charges are decided by the banks after taking into account the cost of inputs.

(c) and (d) With a view to improve the quality of customer services offered by the banks, a Committee under the Chairmanship of Sh. M. N. Goiporia, the then Chairman, State Bank of India was constituted in September, 1990 to study the current state of customer service in banks and to suggest measures to improve the same. The Committee had made wide ranging recommendations covering—

(i) improvement of customer service by enlarging the scope of teller services, extending banking hours for non-cash transactions, devising appropriate procedures to render uninterrupted service during business hours ;

(ii) opening of specialised branches focussing on international banking, industrial finance, small scale industries ;

(iii) technology upgradation and continuous review of systems and procedures in tune with the changing needs of customers ; and

(iv) compensating customers for delay in collection of cheques, payment by mail transfer, telegraphic transfer, etc. Reserve Bank of India have issued instructions to the banks for implementation of the accepted recommendations of the Committee.

तम्बाकू कम्पनियों से वसूल किया गया उत्पादन शुल्क

3762. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू कंपनियों से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई ;

(ख) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने शुल्क की भुगतान नहीं किया है और ऐसी प्रत्येक कम्पनी पर कितनी धनराशि बकाया है ;